

पजेशन शुरू

अब हर महीने रेट बढ़ेगी !

कोठी

₹ 4700/ Sq Ft
से शुरू

वॉक-अप अपार्टमेंट

₹ 4000/ Sq Ft
से शुरू



KEDIA
सेजस्थान

KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड़, जयपुर

बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट

FIXED PRICE & RENTAL

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE	PROPOSED RENTAL
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS	22,000
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS	25,000
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS	28,000
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE	30,000
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.20 CRORE	40,000
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.50 CRORE	50,000

KEDIA®

1800-120-2323

78770-72737

info@kedia.com

www.kedia.com

www.rera.rajasthan.gov.in
RERA No. RAJ/P/2023/2387

SCAN QR FOR

- LOCATION
- ROUTE MAP
- SITE 360 TOUR
- E-BROCHURE
- WALKTHROUGH



*T&C Apply



‘ईडी कार्यवाही आदि, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए की जा रही है’

ममता बनर्जी का खेमा आक्रामक मुद्रा में यह भी कह रहा है कि केन्द्रीय सरकार का यह प्लान हम सफल नहीं होने देंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 जनवरी। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा उफान पर है। ममता बनर्जी ने भाजपा को चुनौती दी है कि वह उन्हें अस्थिर करके दिखाए। वह भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में हैं और हर मोर्चे पर हमला करने के लिए तैयार हैं।

दिल्ली में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़मीन कैसे तैयार कर रही है। ईडी द्वारा आई-पैक के दफ्तर पर छापे के बाद वहां से फाइलें और डेटा उठाने को लेकर भाजपा ममता बनर्जी पर हमला कर रही है।

ममता बनर्जी खुद आई-पैक के दफ्तर पहुंचीं और फाइलें उठा ले गईं। उनका कहना है कि ये फाइलें उनकी

- ऐसा लग रहा है, ममता बनर्जी व केन्द्रीय सरकार के बीच “युद्ध” तब तक चलेगा, जब तक बंगाल चुनाव का अंतिम वोट नहीं पड़ जाता।
- ममता बनर्जी के लोग अपने इस तर्क को आगे ले जाते हुए, यह दावा भी कर रहे हैं कि भाजपा (केन्द्रीय सरकार) के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ममता बनर्जी के वफादार कार्यकर्ता व नेता तथा प्रशासन असक्षम हो जाएंगे, चुनाव में भूमिका निभाने की दृष्टि से तथा भाजपा अपने मन मुताबिक चुनाव का संचालन कर सकेगी और यह ममता बनर्जी के समर्थक, कदापि नहीं होने देंगे।

पार्टी तुणमूल कांग्रेस से जुड़े चुनावी डेटा और चुनावी जानकारीयों से संबंधित हैं, जिन पर अमित शाह की नज़र है।

ईडी ने इस पर सफाई दी है कि

यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी से।

ममता, जिनका लड़ने का जज्बा फिर से जाग उठा है, सड़कों पर उतर

आई हैं और अपने समर्थकों के साथ मार्च कर रही हैं। वह यह संदेश दे रही हैं कि भाजपा जो भी करेगी, वह उससे लड़ने के लिए तैयार हैं और डरने वाली नहीं हैं।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प तलाश रही है, ताकि ममता के वफादारों और उनकी प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग के बिना चुनाव कराए जा सकें और केंद्र की भाजपा सरकार को चुनाव संभालने और उन्हें प्रभावित करने की पूरी छूट मिल सके।

यह लड़ाई आखिरी वोट पड़ने तक चलती रहेगी, जहां भाजपा ममता बनर्जी को अस्थिर करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी और ममता भी उतनी ही दृढ़ता से पश्चिम बंगाल से भाजपा को बाहर करने के लिए डटी रहेंगी।

जैसलमेर में पारा 2.2 डिग्री रहा

जैसलमेर, (निंस्)। शनिवार को जैसलमेर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान प्रदेश के सबसे ठंडे माने जाने वाले हिल स्टेशन माउंट आबू (5.7) से भी कम

- मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक शीत लहर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया।

रहा। उत्तर की बर्फीली हवाओं के कारण सुबह के समय कड़ाके की ठंड का एहसास ज़ोरों डिग्री जैसा हो रहा था। शनिवार अलसुबह जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण चाचा गांव के पास एक निजी बस और पुलिस की गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी में भारी नुकसान हुआ। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही और लोग सुबह देर तक अलाव जलाकर आग तापते देखे गए। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक घना कोहरा और शीत लहर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है।

एसआई भर्ती में आयु सीमा की छूट पर हाई कोर्ट 31 मार्च तक निर्णय लेगा

जयपुर, 10 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को साल 2025 की एसआई भर्ती में आयु सीमा में छूट से जुड़े मामले में दायर एसएलपी को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा है कि 2021 की भर्ती को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले से ही सुनवाई कर रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट से जुड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट की खंडपीठ 31 मार्च से पहले फैसला करे।

- सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर एसएलपी का निस्तारण किया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज मल मीणा की ओर से दायर एसएलपी का निस्तारण करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एसआई 2021 भर्ती को रद्द करने के संबंध में निर्णय हो जाता है तो आयु सीमा का विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि भर्ती रद्द नहीं होती है तो हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के आधार पर आयु सीमा में छूट का फैसला होगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लेकर

पर, आश्चर्य की बात यह है कि ईडी की गुहार में ममता जी को गिरफ्तार करने के लिए मांग नहीं की गई, बल्कि यह मांग की गई है कि ईडी को उसका काम करने दिया जाए, उसमें बाधाएं नहीं होने दें

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 10 जनवरी। अपनी कार्यवाही में लगातार बाधा डाले जाने और कलकता उच्च न्यायालय से कोई राहत न मिलने से खिन्न एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला कई करोड़ रु. के कोयला घोटाले से जुड़ा है, जिसमें एक कंसल्टेंसी फर्म के कार्यालयों में तलाशी और दस्तावेजों की जब्ती की ईडी की कोशिश विफल कर दी गई थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जो किया, ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। वे कोलकाता में आई पैक नामक फर्म के मालिक के आवास और शहर में स्थित उसके मुख्यालय से कथित आपत्तिजनक सामग्री और सबूत अपने

- ईडी ने (केन्द्रीय सरकार ने) इतना नरम रवैया क्यों अख्तियार किया। ममता बनर्जी ने सरकारी एजेंसी के काम में पुलिस की मदद से बाधा पहुंचायी और सबूत के कागजात का “डेटा” उठाकर ले गईं। यह अपने आप में गंभीर जुर्म है और अगर कोई साधारण व्यक्ति यह अपराध करता तो उसे तुरंत जेल भेज कर दंडात्मक कार्यवाही की जाती।

साथ ले गईं। यह पहली बार है जब किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस के साथ आकर ईडी को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने से रोका।

वह भी चक्र गंभीर आर्थिक अपराध के मामले में, जिसमें अवैध कोयला खनन और हवाला लेनदेन के ज़रिये बिक्री की रकम को इधर-उधर करने के आरोप हैं। ईडी यह जांच प्रिवेशन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कर रही थी।

इस तरह का कृत्य कानून की सामान्य प्रक्रिया में ही अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया और कथित तौर पर मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं, वह स्वयं कानून का स्पष्ट उल्लंघन था। वास्तव में उन्होंने राज्य पुलिस के एक दल के साथ ईडी की टीम पर हमला किया और उसे डराने-धमकाने का काम किया, जबकि एजेंसी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत-अमेरिका व्यापारिक वार्ता में अवरोध से भारी घबराहट है निर्यातकों में

निर्यातकों ने भारत सरकार व अमेरिका से वार्ता पुनः शुरू करने का आग्रह किया

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 10 जनवरी। भारत के निर्यातकों ने नई दिल्ली और वाशिंगटन से तत्काल फिर से बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में हो रही देरी से पहले ही नुकसान हो रहा है। और यदि टैरिफ का दबाव और बढ़ा तो यह नुकसान और बढ़ जाएगा। अमेरिका द्वारा चुनिंदा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक का शुल्क लगाए जाने के बाद, उद्योग संगठनों का तर्क है कि दांव पर सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार में उसके निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता भी लगी हुई है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (एफआईओ) के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन के अध्यक्ष एससी रहलन ने निर्यातकों के बीच बढ़ती हताशा और भय का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पक्षों को परस्पर हित के लिए व्यापारिक समझौता करना चाहिए और उससे संबंधित मसलों का समाधान करना चाहिए।
- भारत के कुल निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत अमेरिका को जाता है, इनमें टैक्सटाइल, लैंडर, जवाहरात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, ऑटो पार्ट्स व कैमिकल शामिल हैं। यह क्षेत्र 50 प्रतिशत टैरिफ से पहले ही त्रस्त है और अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो इन वस्तुओं को अमेरिका के बाज़ार से हटना पड़ेगा।

- निर्यातकों का कहना है कि बातचीत में निष्क्रियता से नुकसान बढ़ रहा है, लाभ का मार्जिन सिकुड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऑर्डर कैंसल हो रहे हैं। ट्रेड डील मात्र प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि अस्तित्व से जुड़ी हुई है।

रहा। उत्तर की बर्फीली हवाओं के कारण सुबह के समय कड़ाके की ठंड का एहसास ज़ोरों डिग्री जैसा हो रहा था। शनिवार अलसुबह जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण चाचा गांव के पास एक निजी बस और पुलिस की गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पुलिस की गाड़ी में भारी नुकसान हुआ। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही और लोग सुबह देर तक अलाव जलाकर आग तापते देखे गए। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक घना कोहरा और शीत लहर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 जनवरी। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय अभूतपूर्व पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि राज्य की 29 नगर निकायों में होने वाले चुनावों की तैयारी चल रही है। ये चुनाव तय समय से चार साल की देरी से कराए जा रहे हैं।

इन बदलावों में सबसे अहम है, एक तो अलग हो चुके ठाकरे कज़िन्स (चचेरे भाइयों) का साथ आना और दूसरे प्रतिद्वंद्वी पवार गुटों के बीच सुलह की शुरुआती कोशिशें।

एक ऐसे घटनाक्रम में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने महा विकास अघाडी (एमवीए) गठबंधन से नाता तोड़ते हुए मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ हाथ

- ठाकरे परिवार की एकजुटता मात्र चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि वे बाल ठाकरे की विरासत और “मराठी मानुस” वोट बैंक पुनः पाना चाहते हैं। बीएमसी चुनावों में इस एकजुटता का क्या नतीजा निकलता है, इसी पर आगे का रास्ता निर्भर करेगा।

- एनसीपी के कर्ताधर्ता पवार परिवार में बढ़ती निकटता के पीछे शरद पवार की अपनी बेटी सुप्रिया सुले के भविष्य की चिंता मुख्य कारण है। वे जानते हैं, सुप्रिया उनके भतीजे अजित की तरह जनाधार वाली नेता नहीं हैं।

- यह भी चर्चा है कि एकजुट एनसीपी एनडीए में शामिल हो जाएगी। यहाँ राज्य में अजित पवार मुख्य भूमिका निभाएंगें और राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रिया सुले।

मिला लिया है।

यह साझेदारी केवल चुनावी मजबूरी नहीं है, बल्कि दोनों ठाकरे भाइयों द्वारा मराठी राजनीति के दिग्गज बालासाहेब ठाकरे की विरासत को फिर

से अपने नाम करने की रणनीतिक कोशिश है, जिनका व्यक्तित्व कभी महाराष्ट्र की राजनीति पर छाया हुआ था। इस बात की कल्पना कुछ ही ने की थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना

(यूबीटी) ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए एमवीए से अलग होकर मनसे के साथ गठबंधन करेगा। यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में दूरगामी असर डाल सकता है।

यह गठबंधन सधे हुए चुनावी गणित पर आधारित है। दोनों ठाकरे मिलकर “मराठी मानुस” को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुंबई की आबादी का लगभग 40 प्रतिशत है, वहीं उनकी नजर मुस्लिम समुदाय पर भी है, जो करीब 20 प्रतिशत है, के समर्थन पर भी उनकी नजर है।

इस रणनीति के पीछे सीधा सा तर्क है: एकजुट ठाकरे खेमे का मानना है कि वे कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को हराने की बेहतर स्थिति में हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय के पास उन्हें समर्थन देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री सोमनाथ पहुंचे

वेरावल, 10 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे के तहत सोमनाथ पहुंचे, जहां वे सोमनाथ स्थापिमान पर्व में शामिल हुए। पीएम मोदी आँकार जप में शामिल हुए और झोन शो भी देखा। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,

- वे रविवार को सुबह शौर्य यात्रा में भाग लेंगे।

”सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं, जो हमारी सभ्यतागत साहस का एक गौरवशाली प्रतीक है। गर्मजोशी से स्वागत के लिए लोगों का आभारी हूं। पीएम मोदी रविवार सुबह 9:45 बजे शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। यह एक औपचारिक जुलूस है जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। यात्रा में 108 घोड़ों का एक प्रतीकात्मक जुलूस होगा, जो वीरता और बलिदान को दर्शाता है। इसके बाद, मोदी सुबह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अब रिफॉर्म के बारे में कोई शंका या शुबहा नहीं है। पर, रिफॉर्म्स (उदारीकरण) को कामयाब बनाने के लिए “रेग्युलेटरी सिस्टम” की ज़्यादा जरूरत है।

- बार-बार कायदे कानून बदलना, कायदे कानून के बारे में बहस अभी अनिर्णित है तथा उदारीकरण की नीति को लागू करने के बारे में राज्यों की नीतियों में निर्विवाद प्रक्रिया रही है, अतः क्रियान्वयन समतल नहीं है।

- उदाहरण के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट पार्टियों को भूमिका देना, स्वागत योग्य निर्णय है, पर, प्राइवेट सैक्टर इस क्षेत्र में अपनी पूँजी लगाने के पहले “पारदर्शिता”, विवाद या मतभेद निपटाने की साफ सुथरी व्यवस्था आदि पर कोई दुविधा नहीं चाहेगा।

- अतः किसी ने बड़े सटीक तरीके से इस बारे में कहा है कि “प्र.मंत्री की “रिफॉर्म एक्सप्रेस” को मजबूत पटरियों की ज़्यादा जरूरत है बनिस्पत जोर से बजने वाली सीटी की।”

हुई है, बाहरी मांग धीमी है, स्प्लाइ चेन बदली जा रही है और देश के भीतर लगातार घरेलू असमानता बनी हुई है। इसलिए अमल केवल तकनीकी नहीं,

बल्कि राजनीतिक और संस्थागत चुनौती भी है।

सरकार का भरोसे पर आधारित शासन और निययों में ढील पर ज़ोर देना

सही दिशा में है। भारत की जांच-प्रधान और अनुपालन-भारी (इंस्पेक्टर डिवन) व्यवस्था लंबे समय से उधमता (अपना कारोबार शुरू करने की

ओलंपियन दविंदर सिंह गरचा का निधन

जालंधर 10 जनवरी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी का हिस्सा रहे विजेता दविंदर सिंह गरचा का शनिवार को निधन हो गया। सुरजीत हॉकी सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी इकबाल सिंह संघु ने दविंदर सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बताया कि उनके अंतिम संस्कार की तारीख और समय अभी तय नहीं हुआ है। सुरजीत हॉकी सोसाइटी के सभी सदस्यों ने शोकाकुल परिवार के सदस्यों के साथ संवेदना प्रकट करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि इस अपूर्णीय क्षित को सहने की हिम्मत और शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सात दिसंबर 1952 को जन्मे गरचा उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने 1980 के समर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल छह ओलंपिक मैचों में आठ गोल किए थे और सिर्फ तीन टूर्नामेंट खेलकर 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 19 गोल किए थे। वह मशहूर मोहिंदर सिंह मुंशी हॉकी टूर्नामेंट के अध्यक्ष थे।

फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत पहुंची, दिल्ली में इसका अनावरण किया

नई दिल्ली, 10 जनवरी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी शनिवार को भारत पहुंची , इसका अनावरण शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में ब्राजील के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी गिल्बर्टो सिल्व्वा ने खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे की मौजूदगी में किया। फीफा वर्ल्ड कप 12 साल बाद ट्रॉफी दूर पर भारत लौटा है, इसे दो दिनों तक दिल्ली में रखा जाएगा और उसके बाद इसे भारत से जाने से पहले एक दिन के लिए गुवाहाटी ले जाया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको मिलकर 11 जून से 19 जुलाई तक करेंगे, यह इस चार साल में होने वाले इवेंट का 23वां एडिशन होगा।

हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वस्त्रकर दो हफ्ते के लिए डब्ल्यूपीएल से बाहर

नई दिल्ली 10 जनवरी। भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगी। आरसीबी ने 2026 सीजन का अपना पहला मैच शुक्रवार रात को खेला, जिसमें उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (एमआई) को एक रोमांचक आखिरी ओवर में तीन विकेट से हराया। आरसीबी के हेड कोच मालोलन रंगराजन ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे लगता है।

राजधानी

राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने किया पुस्तक ‘‘मेरी मुलाकातें’’ का लोकार्पण

जयपुर। विश्व हिंदी दिवस के पावन अवसर पर सिविल लाईंस विधायक एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉ. गोपाल शर्मा की नई पुस्तक ‘‘मेरी मुलाकातें’’ का लोकार्पण शनिवार को राज्यपाल बागडे और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी), झालाना में आयोजित समारोह में किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समारोह को वचुंअल माध्यम से जुड़े। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक की भूमिका राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने लिखी थी। पुस्तक में डॉ. शर्मा के लंबे पत्रकारीय यात्रा की प्रमुख मुलाकातें, राजनीतिक एवं साहित्यिक वृत्तांत समाहित हैं, जो पाठकों को इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों से रूबरू कराती हैं। समारोह को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपने आशीर्वाचनों से सम्मानित किया, जबकि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री



राज्यपाल बागडे और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने हिंदी दिवस के पावन अवसर पर 'मेरी मुलाकातें' का लोकार्पण किया।

अश्विनी वैष्णव ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी समारोह को संबोधित किया। विधायक गोपाल शर्मा ने स्वागत उद्बोधन के साथ पुस्तक में शामिल साक्षत्कारों से जुड़े संस्मरण साझा किए। अमर शहीद भगत सिंह के

भतीजे किरणजीत सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व पंचअनवर खां मांगणियार ने अपने साथियों के साथ सूफी भजन की मनमोहक प्रस्तुति दी। गोपाल शर्मा का पत्रकारीय जीवन प्रेरणास्त्रोत : राज्यपाल बागडे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा

कि विधायक गोपाल शर्मा का पत्रकारीय जीवन आदर्श पूर्ण रहा है, जो कि नए पत्रकारों लिए एक संभव भरा मार्गदर्शन और प्रेरणास्त्रोत है। इन्होंने अपने पत्रकारिता के दौरान उस दौर के सभी राजनीतिक दिग्गजों, सामाजिक और अति विशिष्ठ व्यक्तियों से मिलकर जो उनके

- पुस्तक में डॉ. शर्मा के लंबे पत्रकारीय यात्रा की प्रमुख राजनीतिक एवं साहित्यिक वृत्तांत समाहित हैं, जो पाठकों को इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों से रूबरू कराती हैं

साक्षात्कार किए, वे बहुत सराहनीय हैं। कई साक्षात्कार तो ऐसे हैं जिनसे मुलाकात के बारे में सोचना भी उस वक्त कठिन था। राज्यपाल ने पत्रकारिता में साक्षात्कार विधा को समय के दस्तावेज बताते हुए कहा कि साक्षात्कार वही सार्थक होते हैं, जिनमें लेने और देने वाला दोनों ही कृषय और सामयिक संदर्भों के मर्मज्ञ हों। उन्होंने विश्वास जताया कि गोपाल शर्मा की लिखी पुस्तक से पाठक लाभान्वित होंगे।

पावटा में फ्लाईओवर के लिए टीम ने जायजा लिया

पावटा. दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा कस्बे में बढ़ ते जाम से निजात दिलाने को लेकर पूर्व विधायक सुभाष चन्द्र शर्मा ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं संकीर्ण निर्माण के चलते प्रतिदिन भारी जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कस्बे का सामान्य अंडरपास निर्माण की मांग की है।

शर्मा ने पत्र में बताया कि पावटा उपखण्ड मुख्यालय पर राजमार्ग निर्माण के दौरान पूर्व में एक अत्यंत छोटा अंडरपास बनाया गया था। संकीर्ण निर्माण के चलते प्रतिदिन भारी जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कस्बे का सामान्य आवागमन प्रभावित रहता है।

जन स्वास्थ्य मंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शनिवार को डीडवला-कुचामन जिले के कुचामन तहसील मुख्यालय के ग्राम पंचायत जसराना में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सम्बंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए । रात्रि चौपाल में ग्रामीणों द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष ग्राम पंचायत एवं ढाणियों में पेयजल आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन,सड़क निर्माण, रास्ते पर अतिक्रमण, सामाजिक सुरक्षा पंन्, स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को पट्टे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति सहित अन्य लाभ प्रदान किये।

इस दौरान प्रभारी मंत्री चौधरी ने ग्रामीणों से संवाद कर राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों एवं वीबी- जौ रामजी के बारे जानकारी दी।

‘आदेश की पालना करो, वरना वीसी हो हाईकोर्ट में पेश’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय कर्मचारी को बकाया भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि आगामी सुनवाई तक अदालती आदेश की पालना की जाए।ऐसा नहीं करने पर अदालत ने विवि के कुलगुरु को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए 29 जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार न्यायिक को कहा है कि वह आदेश की प्रति वीसी कार्यालय में तत्काल भेजें, ताकि आदेश की पालना सुनिश्चित की जा सके। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश राजकुमार वर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने

- अदालत ने विवि के कुलगुरु को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए 29 जनवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं

पेश होकर अदालत को बताया कि उसकी ओर से अपनी सेवा के नियमोत्तरण और उससे जुड़े लाभ के लिए याचिका दायर की थी। जिसके एकलपीठ ने 26 नवंबर, 2021 को स्वीकार करते हुमें याचिकाकर्ता को नियमित करने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ विवि प्रशासन ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। खंडपीठ ने 28 मार्च, 2022 को अपील का निस्तारण करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता की

सेवा को उस दिन से नियमित माना जाए, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमित किया गया था। अवमानना याचिका में कहा गया कि खंडपीठ के आदेश की पालना में विवि ने उसकी सेवा को नियमित कर दिया, लेकिन संपूर्ण वित्तीय लाभ और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। ऐसे में अदालती आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों को दंडित करते हुए आदेश की पालना कराई जाए। वहीं विवि की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के संबंध में वित्तीय स्वीकृति का मामला राज्य सरकार के समक्ष लंबित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आगामी सुनवाई तक आदेश की पालना नहीं करने पर विवि के कुलगुरु को वीसी या व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा है।

मानसरोवर दुर्घटना दुखद, समाज में जागरूकता आवश्यक : मदन राठौड़

- आरएसएस के प्रातः स्मरण में भी महात्मा गांधी को किया जाता है याद, कांग्रेस ने गांधी के नाम पर सेंकी राजनीतिक रोटियां : मदन राठौड़

से कुशलक्षेम जानी और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी का सम्मान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस एक आंदोलन है, और देश आज़ाद होने के

बाद इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के मूल स्वरूप को समाप्त कर दिया गया। पहले दो बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह था, फिर गाय-बछड़ा, और अब हाथ का पंजा-यह किस विचारधारा की कांग्रेस है, यह सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रातः स्मरण में भी महात्मा गांधी सहित महापुरुषों को स्मरण किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम गांधीवादी समाज को मानते हैं, लेकिन गांधी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का विरोध करते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीबी जी – राम जी (विकसित भारत – गारटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण) योजना पर बोलते हुए कहा कि यदि योजना के नाम में राम का नाम आता है, तो उस पर आपत्ति क्यों की जा रही है।

अमित शाह ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई , पेपर लीक समाप्त करने की प्रशंसा की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आरपीए में आयोजित समारोह में आठ हजार नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्त पत्र दिए

जयपुर, 1० जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से लोकसेवकों की भर्ती करने से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को इससे निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत व कुशल नेतृत्व मिल रहा है।**

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान करते हुए राजस्थान के युवाओं को 'बिना सिफारिश और बिना खर्च' के नौकरी दे रही है।

शाह शनिवार को आरपीए में कांस्टेबल नव नियुक्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पेपरलीक पर रोक लगाने के साथ-साथ



केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को आरपीए में आयोजित कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह को संबोधित किया।

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में निवेश का अग्रणी राज्य बनाने का काम भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज देशभर के निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल

रहा है। धारा 37० को हटाने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती देने का काम किया गया। शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद का सफाया करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया।

शाह ने कार्यक्रम में संकेतिक रूप से 1० आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 8 हजार से अधिक आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

गए। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बने मल्टी परपज इंडोर हॉल का वर्युअल लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदू म, सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधिकाीरगण, बड़ी संख्या में नव नियुक्त कांस्टेबल एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

ट्रंप ने ईरान में सैन्य हस्तक्षेप के संकेत दिए परन्तु ट्रंप ने यह भी कहा कि वह जमीन पर सैनिक नहीं उतारेंगे

वॉशिंगटन, 1० जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि अगर ईरान वर्तमान अशांति के इस दौर में लोगों को मारना शुरू कर देता है तो अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा, हालांकि वह जमीन पर अपने सैनिकों की नैनाती नहीं करेगा।

ईरान की स्थिति पर संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो ऐसा होने पर अमेरिका अपनी भूमिका निभायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपनी फौजें, ईरान की जमीन पर उतार देगा। इसका अर्थ यह है कि उन्हें वहां बहुत जोर से मारना है, जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। ट्रम्प और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने

- ट्रंप ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही जनता पर हमला किया गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।**

बार-बार चेतावनी दी है कि यदि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, तो वॉशिंगटन कार्रवाई करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अशांति के बारे में ट्रम्प प्रशासन की टिप्पणियों को हस्तक्षेपवादी और भ्रामक बताते हुए उनका निंदा की थी। ईरान का कहना है कि ये बयान ईरानी लोगों के प्रति अमेरिका की निरंतर शत्रुता को दर्शाते हैं।

एसआई भर्ती ...

गुहार की थी। एकलपीठ ने तीस अक्टूबर, 2०25 को इन अर्थर्थियों को भर्ती में तीन साल की छूट देने को कहा। वहीं राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर गत 13 नवंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी।

पुणे निगम चुनाव के लिए सुप्रिया व अजित पवार ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया

मुंबई, 1० जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष अजीत पवार और राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवारको पुणे के शिवाजीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी

- भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्य होने के बाद भी अजित पवार ने केन्द्र व राज्य सरकार की आलोचना की**

किया। इस संयुक्त घोषणापत्र में पुणे में मुप्त मेट्रो और बस यात्रा का वादा किया गया है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, “पुणेवासी सवाल कर सकते हैं कि क्या मुप्त मेट्रो और बस यात्रा संभव भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संभव है। हमने विशेषज्ञों से बात करने के बाद इस में फैसला किया है। हम पुणे और पिंपरी-चिंचवड् के निवासियों को मुप्त मेट्रो रेलवे और बस यात्रा प्रदान करेंगे।”

घोषणापत्र में पुणे नगर निगम के स्कूलों के छात्रों को मुप्त टैबलेट देने के साथ-साथ पुणे में 15० मॉडल स्कूल स्थापित करने का वादा किया गया है।

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “पुणे के पांच साल के विकास का मुद्दा हमारे सामने है। मुप्त यात्रा प्रदान करना संभव है। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के प्रशासन में कुछ गलतियां हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा।”

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिठ्ठी लिखी

कोलकाता, 1० जनवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आम नागरिकों के साथ किए जा रहे निरंतर उल्टीड़न पर हैरानी और पीड़ा व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में आरोप लगाया है कि इस पुनरीक्षण अभ्यास के कारण 77 मौतें, आत्महत्या के चार प्रयास और कम से कम 17 लोगों के बीमार होने व अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई

देवली में तीन करोड़ रूपए का गांजा जब्त

- पुलिस ने नाकाबंदी कर उड़ीसा से आ रहे ट्रूक में 500 किलो गांजा पकड़ा।**

किया है। देवली पुलिस थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भागव, पुर्बेन्द्र सोलंकी और डीएसपी हेमराज के सुपरविजन में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश की टीम ने देवली हाईवे पर घेराबंदी की थी। इसी के चलते पुलिस को देखते ही तस्करी ने ट्रक को टोंक की ओर भगाकर ले जाने की कोशिश

ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों पर मशीनगन से गोलियां चलाई

गोलीबारी में 217 प्रदर्शनकारी मारे गये, सरकार विरोधी आंदोलन और उग्र हुआ

- अगर मृतकों की संख्या की सही पुष्टि हो जाती है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि सरकार 28 दिसंबर से सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारियों को मारती है, तो उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।**

तेहरान, 1० जनवरी। तेहरान में ईरान सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में हिंसा बढ़ गई है। प्रदर्शन उग्र होता देख ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी में 217 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है।

दरअसल, एक स्थानीय डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर टाइम पत्रिका को बताया कि राजधानी के सिर्फ छह अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। इसमें अधिकांश की मौत गोली लगने से हुई है। जनसंख्या डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में अधिकतर युवा थे, जिनमें उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने के दौरान मारे गए कई लोग शामिल थे। इन सभी

है। उन्होंने कहा, "ये घटनाएं डर, डराने-धमकाने और अवैधिक कार्यकार का परिणाम

प्र.मंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों ...

- बनर्जी ने नोबल पुरस्कार विजेता अमर्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, फिल्म एक्टर व सांसद दीपक अधिकारी जैसी कई हस्तियों का मुद्दा उठाया, जिन्हें चुनाव आयोग के सामने अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी।**

- मुख्यमंत्री ने टाइप की हुई चिठ्ठी के साथ एक हस्तालिखित नोट भी भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि “मुझे” पता है आप ना तो जवाब देंगे ना ही स्पटीकरण देंगे पर विवरण देना मेरा कर्तव्य है।**

है। उन्होंने कहा, "ये घटनाएं डर, डराने-धमकाने और अवैधिक कार्यकार का परिणाम

हैं। प्रशासनिक क्षमता में निवेश किए बिना तेज और पुणवत्तापूर्ण नतीजों की उम्मीद सुधारों के असेर को कमजोर कर सकती है और निराशा बढ़ा सकती है।

निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा खोलने जैसे बड़े कदम सरकार की मंशा की गंभीरता दिखाते हैं। लेकिन निजी पूंजी बहुत सख्त मानकों पर काम करती है। उसे साफ नियम, भरोसेमंद विवाद, समाधान व्यवस्था और स्थिर नीतिगत माहौल चाहिए। घोषणाओं के साथ विस्तृत नियमावली और संस्थागत भरोसा भी होना चाहिए वरना इनके बदले निवेश आने की जगह सर्तकता और झिझक ही देखने को मिलेगी।

व्यापार समझौते भी बिखरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर व्यावहारिक सोच दिखाते हैं। लेकिन व्यापार उदारीकरण के साथ समायोजन की लागत आती है। लॉजिस्टिक्स,

कौशल विकास और सस्ते ऋण में समानांतर निवेश के बिना, खासकर छोटे भारतीय उद्योग खुलते बाजार में टिक नहीं पाएंगे।

आखिरकार, इस सुधार चक्र की मजबूती इस बात पर निर्भर होगी कि इसके फायदे आम लोगों तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर विकास के साफ तौर पर रोजगार, आय में बढ़ोतरी और क्षेत्रीय संतुलन नहीं दिखता, तो सुधारों के लिए जरूरी सामाजिक और राजनीतिक सहमति कमजोर पड़ सकती है।

रमत्तर जरूरी है। लेकिन अगर 2०25 को एक ऐतिहासिक साल के रूप में याद किया जाना है, तो यह इसलिए होगा क्योंकि सुधारों को समझदारी से लागू किया गया, संस्थानों को मजबूत किया गया और जनता का विश्वास हासिल किया गया, केवल इसलिए नहीं कि वे तेज चले।